नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

डिजिटल अरेस्ट : सरकार की बहु-स्तरीय योजना

डिजिटल युग ने जहां नागरिकों को अभूतपूर्व सुविधाएं दी हैं, वहीं साइबर अपराधों के नए-नए रूप भी सामने आए हैं. इन्हीं में से एक है तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट', जो कानूनन अस्तित्वहीन होने के बावजूद भय, भ्रम और तकनीकी अज्ञानता के सहारे लोगों को ठगने का बड़ा माध्यम बन चुका है. वीडियो कॉल पर वर्दीधारी चेहरों का डर, फर्जी नोटिस और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव,यह सब एक संगठित साइबर अपराध तंत्र का हिस्सा है. इस गंभीर चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बहु-आयामी रणनीति के जरिए इस पर लगाम लगाने का प्रयास तेज कर दिया है.

सरकार की इस रणनीति की रीढ़ है अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी), जिसका गठन दिसंबर 2025 में किया गया. गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, आरबीआई और खुफिया एजेंसियों को एक मंच पर लाकर यह समिति 'रियल-टाइम' समाधान पर काम कर रही है. पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजनों को सीधे जिम्मेदार भागीदार बनाया गया है, ताकि व्हाट्सएप, स्काइपे जैसे माध्यमों पर सक्रिय संदिग्ध खातों को बिना देरी ब्लॉक किया जा सके. यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार अब साइबर अपराध को केवल पुलिसिंग का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी गवर्नेंस का मुद्दा मान रही है.

दूसरी बड़ी पहल है सीबीआई को दी गई खुली छूट. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम की जांच में अब आधे-अधूरे हाथ नहीं, बल्कि पूरा अधिकार दिया गया है. खास बात यह है कि जांच का दायरा केवल ठगों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन बैंक कर्मचारियों तक भी पहुंच रहा है जो 'म्यूल अकाउंट' खोलने में भूमिका निभाते हैं. यह संदेश स्पष्ट है,सिस्टम के भीतर मौजूद कमजोर कड़ी अब जांच से बाहर नहीं रहेगी. वहीं इंटरपोल के साथ सहयोग बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश इस अपराध की वैश्विक प्रकृति को स्वीकार करने का प्रमाण है.

तकनीकी मोर्चे पर आई बार सी और डीओटी की भूमिका निर्णायक बनकर उभरी है. स्पूफ कॉल्स, जो विदेश से होकर भी भारतीय नंबर दिखाती हैं,अब पहले जैसी सहजता से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं. लाखों सिम काई, आईएमईआई नंबर और हजारों डिजिटल अकाउंट का ब्लॉक होना बताता है कि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं है. इसके साथ ही इसे सरकारी डिजिटल प्लेटफार्म्स से भी जोड़ा गया है. संदिग्ध यूपीआई या नंबर को पहले ही जांच सकना साइबर सुरक्षा में जन-भागीदारी का महत्वपूर्ण कदम है. इस पूरी कवायद को मजबूती देता है 782 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान और राज्यों में क्षेत्रीय साइबर अपराध केंद्रों को सशक्त करने की योजना. यह स्वीकारोक्ति है कि साइबर अपराध का मुकाबला केवल केंद्र से नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर मजबूत ढांचे से ही संभव है.

सबसे अहम संदेश, जिसे बार-बार दोहराने की जरूरत है, भारत के किसी भी कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसा कोई प्रावधान नहीं है. न पुलिस वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी करती है, न ही कोई सरकारी एजेंसी पैसे मांगती है. सरकार द्वारा गूगल, एआई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संवाद इस दिशा में सही कदम है, लेकिन अंतिम सुरक्षा कवच जागरूक नागरिक ही है. डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ यह लड़ाई केवल तकनीक या कानून की नहीं, बल्कि भरोसे और जानकारी की है. सरकार की बहु-स्तरीय रणनीति उम्मीद जगाती है, पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डर के इस डिजिटल जाल को हम कितनी समझदारी से पहचान पाते हैं.

ताक पर संवैधानिक शुचिता अनुचित

'दीदी' की 'चोरी और सीनाजोरी'

विजय कुमार झा

लोकतंत्र की मर्यादा और संवैधानिक शुचिता को ताक पर रखकर पश्चिम बंगाल में जो तमाशा हो रहा है, उसे राजनीति के गिरते स्तर की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के विरुद्ध जिस तरह का आचरण किया है, वह 'चोरी और सीनाजोरी' की कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है.

कोयला घोटाले से जुड़े मामले में आई-पैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री का स्वयं वहां पहुंचना, जांच अधिकारियों से फाइलें छीनना और फिर स्थानीय पुलिस की मदद से गोपनीय सामग्रियों को अपने कब्जे में लेना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है. सवाल यह है कि यदि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने कुछ गलत नहीं किया था, तो केंद्रीय एजेंसी की जांच से इतनी बौखलाहट क्यों? संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जब खुद कानून के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाए, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी.

इस पूरे घटनाक्रम में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ईडी ने तृणमूल कांग्रेस की चुनाव संबंधी फाइलें जब्त की हैं, जबकि जांच एजेंसी का स्पष्ट कहना है कि यह कार्रवाई करोड़ों के कोयला घोटाले से जुड़ी है. दिलचस्प बात तो यह है कि यदि वे फाइलें चुनाव संबंधी थीं, तो वे किसी निजी कंपनी या आई-पैक के दफ्तर में क्या कर रही थीं? इस एक सवाल ने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है. दिल्ली में गृह मंत्री के कक्ष के बाहर तृणमूल सांसदों का हंगामा और सड़क पर उतरकर समर्थकों द्वारा जांच को प्रभावित करने की कोशिशें यह बताती हैं कि वहां शासन नहीं, बल्कि सत्ता की हनक से व्यवस्था को हांकने का प्रयास हो रहा है.

राज्यपाल सीबी आनंदबोस ने इस मामले का संज्ञान लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेजने की बात कही है, जो बंगाल में बिगड़ते संवैधानिक संतुलन की पुष्टि करता है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी जान-बूझकर केंद्र और चुनाव आयोग से टकराव का ऐसा माहौल बना रही हैं, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति पैदा हो जाए. यह सहानुभूति बटोरने की एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है, लेकिन इसके लिए कानून की धज्जियां उड़ाना और केंद्रीय एजेंसियों के काम में बाधा डालना न्यायसंगत नहीं है. ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. एजेंसी की यह दलील बेहद गंभीर है कि यदि अदालती संरक्षण नहीं मिला, तो राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का स्वतंत्र रूप से काम करना असंभव हो जाएगा.

बंगाल सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर अपनी तैयारी दिखाई है, लेकिन नैतिकता के मोर्चे पर वह पिछड़ती नजर आ रही है. किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का पालन सुनिश्चित कराएंगी, न कि स्वयं कानून को हाथ में लेकर फाइलों की छीनाझपटी करेंगी. विचारधारा का विरोध राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जांच में बाधा डालना विशुद्ध रूप से अमर्यादित आचरण है. अब जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां से ऐसा संदेश निकलेगा, जो संघीय ढांचे में राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच की गरिमा को पुनर्स्थापित करेगा.

बंगाल की धरती, जो कभी अपनी संस्कृति और बौद्धिक चेतना के लिए जानी जाती थी, आज राजनीतिक अराजकता का केंद्र बन गई है. सत्ता की इस लड़ाई में यदि संविधान और कानून हार गए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

महाकौशल की डायरी

भाजपा जिला उपाध्यक्ष के इस्तीफे की गूंज भोपाल पहुंची

अविनाश दीक्षित

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर को हाल ही में जिला उपाध्यक्ष बनी अंजू भार्गव ने अपने पद से इस्तीफा पत्र सौंपा उसके कुछ घंटे बाद ही शहर के ईसाई समाज ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया. अब ये खुशी तथाकथित धर्मांतरण विवाद से संबंधित रही या फिर जिला उपाध्यक्ष के पद को खाली कराकर अपने आदमी को सेट करने की, इसका राज अभी भी बरकरार है लेकिन पार्टी सूत्रों की मानें तो एक पक्ष ने जिला उपाध्यक्ष पर इस्तीफे का दवाब बनाया जिससे उस सीट पर दूसरा कोई उनका आदमी सेट हो सके. भाजपा जिला उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए इस्तीफे की गूंज भोपाल तक प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक पहुंची तो शहर में पार्टी के शीर्ष नेताओं को फटकार भी सुनने मिली . क्योंकि सभी जानकारों की सहमति से जिला उपाध्यक्ष पद पर अंजू भार्गव को चयनित किया गया था उसके बाद भी जो हालात पिछले कुछ दिनों पहले सामने आए उसने भाजपा की अंतर्कलह को सभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया.

दूसरी तरफ पार्टी के जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने भी दबी जुबान से कहा कि अंजू भार्गव ने इस्तीफा देकर बड़प्पन का काम किया है क्योंकि वे तथाकथित धर्मांतरण के आरोप को लेकर एक दृष्टिहीन महिला से हुए विवाद में पार्टी की छवि धूमिल नहीं करना चाहती थीं. ऐसे में शहर के राजनैतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं कि भाजपा की नगर उपाध्यक्ष ने इस्तीफा तो दे दिया है लेकिन उस इस्तीफे के पीछे पार्टी के कुछ नेताओं की प्रेशर पॉलिटिक्स की भूमिका ज्यादा रही. राजनैतिक जानकारों की मानें तो भाजपा नगर उपाध्यक्ष की नियुक्ति के पहले स्थानीय संगठन के दिग्गजों से राय शुमारी भी की गई थी किसे कौन सा पद देना है जो आगामी चुनावों में संगठन को लाभ पहुंचाएगा. कई दिनों तक चली रायशुमारी के बाद जो लिस्ट फाइनल हुई उस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अंत में मुहर लगाकर सूची सार्वजनिक कर दी थी. ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सब कुछ रायशुमारी से किया गया तो नियुक्ति के कुछ ही दिनों में इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा हो गया. चर्चाएं तो ये भी हैं कि जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव की नियुक्ति से भाजपा के ही कई नेता, पदाधिकारी संतुष्ट नहीं थे और वे चाहते थे कि अंजू की जगह किसी दूसरे सक्रिय नेता को नगर उपाध्यक्ष की कमान सौंपी जाए.

कांग्रेसी पार्षद ने अपनी ही पार्टी के अभियान में लगाया पलीता

हाल ही में जबलपुर का सियासी माहौल उस वक्त गरमा गया जब विपक्ष यानि कांग्रेस के पार्षद वकील अंसारी ने सार्वजनिक तौर पर निगमायुक्त, महापौर व सत्ता पक्ष की पेयजल को लेकर प्रशंसा कर दी. एक ओर जहां कांग्रेस के स्थानीय दिग्गज नेताओं ने कांग्रेसी पार्षद की इस कारनामे पर चुप्पी साधी हुई है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पार्षद ने ऐसा करके पार्टी की एकजुटता, अनुशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया. चर्चाएं जोरों पर थीं कि शहर में दूषित पानी को लेकर भाजपा को घेरने चली कांग्रेस ऐडी चोटी का जोर लगा रही है तो फिर कांग्रेस के ही पार्षद को इस अभियान में अड़ंगा नहीं डालना था.

जब उमंग सिंगार को आया गुस्सा....

जब किसी के घर कोई मेहमान आ रहा है तो हमें बिना बुलाए वहां नहीं ठसना चाहिए. यदि आप ऐसा करते हैं तो अपमान होना स्वाभाविक सी बात है. कुछ ऐसा ही वाक्या महाकौशल के सिवनी में हाल ही में घटित हुआ, जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को गुस्सा आया और उन्होंने जिला कांग्रेस के बड़े पद पर विराजमान एक कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी विधायक से कहा कि आप दोनों के मोजे से बदबू आ रही है, आप यहां से उठो. बस फिर क्या था दोनों कांग्रेसी अपना मुंह लटकाकर नेता प्रतिपक्ष के कमरे से बाहर आ गए. हुआ यूं कि सिवनी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक अन्य जिले के कांग्रेस अध्यक्ष के रिश्तेदार के घर मिलने पहुंचे थे तभी अपने नंबर बढ़ाने के लिए दो कांग्रेसी नेता वहां पहुंच गए. लेकिन जब दोनों के मोजे से दुर्गन्ध आई तो उन्हें शर्मिंदा होकर बाहर आना पड़ा. बताया जा रहा है कि कांग्रेसी नेताओं के मोजों से बदबू आने में दोनों की कोई गलती नहीं थी क्योंकि दोनों ही नेता प्रतिपक्ष की अगवानी करने सुबह से लगे हुए थे और नए मोजे पहनना भूल गए थे. खबर तो ये भी है कि इन दोनों कांग्रेसियों को इस घटना से सबक मिल गया है और अब दोनों से बिना बुलाए कहीं भी जाने से स्पष्ट मना करने लगे हैं.

अब जिला परिषद-पंचायत चुनाव की बारी

आखिर जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ऐसी 12 जिला परिषदों व 125 पंचायत समितियों का चुनाव कराने के लिए 15 फरवरी तक की नई मुद्दत दी, जहां आरक्षण की बाधा नहीं है. तदनुसार आयोग ने 5 फरवरी को मतदान व 7 फरवरी को मतगणना का कार्यक्रम तय किया. इस तरह अब राज्य में 30 जिला परिषदों व 211 पंचायत समितियों का चुनाव लटका हुआ है. कोंकण, पुणे व मराठवाडा विभाग की जिला परिषदों व पंचायत समितियों के लिए मतदान होगा लेकिन ओबीसी आबादी बढ़ने की वजह से विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होगा. जहां चुनाव होगा वहां आचार संहिता लागू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्णय के अनुसार अजा-अजजा को संविधान प्रदत्त आरक्षण छोड़कर 50 प्रतिशत सीमा के भीतर जितना संभव हो ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए. इस वजह से जिला परिषद में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गंभीर हो गया है. 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा रहने से ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम होगा. बढ़ी हुई आरक्षित सीटों के मुद्दे पर 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. आधी से ज्यादा जिला परिषदों का चुनाव अटका हुआ है. पहले 288 छोटे शहरों में नगरपालिका व नगरपंचायत का चुनाव हुआ फिर महापालिका का चुनाव 15 जनवरी को हो रहा है. इसके बाद जिला परिषद का चुनाव होगा. इस तरह निर्वाचन का यह सिलसिला जारी है. लगभग 2 महीने से राज्य का संपूर्ण प्रशासन व सरकारी मशीनरी चुनाव कार्य में लगी हुई है. आचार संहिता भी लागू है. वित्त वर्ष समाप्त होने की ओर है लेकिन अनेक सरकारी योजनाओं का काम रुका हुआ है. प्रशासकीय मशीनरी को चिंता है कि वार्षिक योजना निधि कैसे खर्च की जाए. यदि शेष जिला परिषदों का चुनाव कराने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो आचार संहिता मार्च में भी लागू रहेगी. इसी दौरान 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं भी होंगी. चुनाव प्रचार के शोर से विद्यार्थियों का नुकसान होगा.

निशानेबाज

वोटिंग में विवेक का करें इस्तेमाल घोषणापत्रों में वादों का जाल

पड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज आप अध्ययनशील हैं, इसलिए हर पार्टी या गठबंधन के चुनाव घोषणापत्र का अवश्य ही बारीकी से अध्ययन करते होंगे. इससे आपका ज्ञान बढ़ता होगा कि हमारी पार्टियों को जनता की कितनी फिक्र है और वो कितना जनकल्याण करना चाहती हैं.'

हमने कहा, 'चाहे चुनावी वचननामा हो या नेताओं के भाषण में दिए गए लुभावने आश्वासन, ये सब मौसमी बुखार की तरह हैं. भोले भाले लोग आंख मूंदकर इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं. ऐसे हवा-हवाई वादों को ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेता सपनों के सौदागर होते हैं जिनका काम आकर्षक सपने दिखाने का है. चुनाव के समय ये लोग जनता के आशिक बन जाते हैं, बाद में सारी प्यार-मोहब्बत भूल जाते हैं. उनके आश्वासन स्टैंप पेपर पर लिखे प्रॉमेसरी नोट नहीं रहते. चुनावी वादे का कोई कानूनी आधार नहीं होता. यह बंधनकारी नहीं होते. वचन देने में नेता कोई कंजूसी नहीं करता.'

पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, नेताओं की दरियादिली पर इतना अविश्वास मत कीजिए. लोगों को भरोसा है तभी तो उत्साहपूर्वक वोट डालने जाते हैं और लाइन में खड़े होकर मतदान की अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं.'

हमने कहा, 'उंगली पर अमिट स्याही तो लगा दी जाती है लेकिन चुनावी वादे अमिट नहीं होते. सत्ता पक्ष के नेता जब बड़े-बड़े आश्वासन देते हैंतो चादर देखकर पैर नहीं पसारते. सरकारी खजाने में इतने पैसे नहीं होते कि सारे खैराती वादे पूरे कर दिए जाएं. विपक्षी पार्टियों का मुख्य लक्ष्य सत्ता हासिल करना होता है इसलिए वह भी वादों की हवा भरकर रंगबिरंगा गुब्बारा फुलाती हैं. इसलिए सोच समझकर विवेकपूर्वक मतदान अवश्य कीजिए. यह आपका लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य है. आजाद मुल्क के नागरिकों के लिए वोटिंग का अधिकार एक नियामत है. वोटर का मेंडेट या जनादेश ही तय करता है कि वह किसे सत्ता पर देखना चाहता है. मतदान के दिन को छुट्टी मिलने, तफरीह करने में बिताने का इरादा बाद में कीजिए. पहले जल्दी से जल्दी जाकर वोट डालिए. अपनी मर्जी से मतदान करते समय किसी भी दबाव या प्रलोभन में हरगिज न आएं. नेताओं को परखने का यही सही अवसर है. जो वोट नहीं डालते, उन्हें बाद में शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है.'

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 12143 - डॉ. सागर खादीवाला

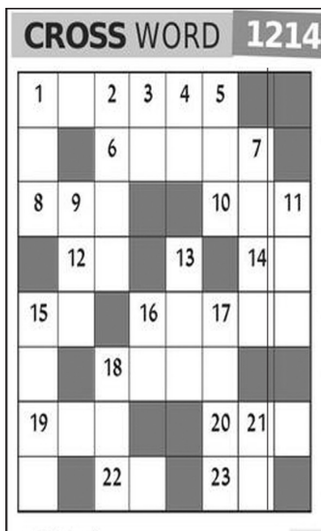

ऊपर से नीचे

1. हाव भाव, नाज-नखरा 2. चिरना 3. धूल, गर्द, पराग (सं.) 4. वैद्यक के अनुसार शरीर की वह वायु जिसके विकार से रोग उत्पन्न होते हैं 5. जप करने वाला 7. एक फल जिसकी तरकारी बनती है 9. जैसा है वैसा, ठीक, सत्य 11. नष्ट होना, भागना 13. सांचे में ढाला जाना, बीत जाना 15. अंगहीन, काम न करने योग्य 16. लपलपाने की क्रिया या भाव, अंजली भर कोई चीज 17. काम अथवा उद्योग में लगा रहने वाला 18. फालतू, बचा

बाएं से दाएं

1. गुप्त द्वार 6. वह श्वेत पर्दा जिस पर चलचित्र दिखाया जाता है 8. योग्य, उचित, ठीक, गुणवान (उर्दू) 10. धनुष, मेहराब (उर्दू) 12. पुलिस की चौकी 14. भारी वस्तु के सरकने का शब्द 15. शब्द का अभिप्राय, मतलब 16. लड़ने के लिए चिल्लाकर बुलाना 18. नाम के अतिरिक्त अन्य नाम, उपाधि-पदवी 19. गणित संबंधी प्रश्न, लेन-देन आय-व्यय आदि का लिखा हुआ वर्णन (उर्दू) 20. योग्य, विद्वान (उर्दू) 22. मार्ग 23. जीवित रहना, सीढ़ी

Solution 12142

पि	रा	मि	ड		ध		ऊ
च	ल	न		अ	म	रू	द
का		ट	क	ट	की		बि
री	म		था	ल		खा	ला
	हा	नि			मा	न	व
अ	प्र	का	शि	त		दा	
क	ल	ह		ग	जा	न	न
रा	य		भि	ड़ा	ना		ट

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष केप्रारंभ में अचानक धन लाभ का योग है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वर्ष के मध्य में राजनैतिक क्षेत्र में विवाद के कारण मन खिन्न रहेगा, साझेदारी में विवाद बढ़ेगा, धन संकट का सामना करना होगा, वर्ष के अन्त में व्यक्तिगत संबंधों मेंसुधार होगा, मित्रों के सहयोग से लाभ होगा.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों से धन संकट का सामना करना पड़ेगा, वृष और तुला राशि के व्यक्तियों का साझेदारी में विवाद बढ़ेगा, कर्क राशि के व्यक्तियों को मित्रों का सहयोग, व्यापार मं वृद्धि होगी, मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को सहयोग प्राप्त होगा, सिंह राशि के व्यक्तियों को राजनैतिक मित्रों की मदद मिलेगी, धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को निजी पुरूषार्थ की प्राप्त होगी, मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को मित्रों का सहयोग रहेगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिये बालक संकोची, एकांतप्रिय, परोपकारी तथा मधुरभाषी होगा. शिक्षा उत्तम रहेगी. नौकरी में सफ्लता प्राप्त करेगा. जन्म स्थान से दूर अपना भाग्योदय करेगा. आय के एक से अधिक साधान रहेंगे. माता पिता का भक्त होगा.

मेष- समय पर काम पूरा नहीं होने से अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी. मानसिक संतुलन बना रहेगा. लाभदायक अवसर प्राप्त होने का योग है.

वृषभ- अपनों के व्यवहार से खिन्नता होगी. मामूली बातों को तूल देने से रिश्तों में दरार पड़ सकती है. शारीरिक पीडा हो सकती है. परिश्रम रहेगा.

मिथुन- भाग्योदय के अवसर मिलेंगे. पुराने मामले सुलझेंगे. धार्मिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. आजीविका प्रयासों में सफ्लता मिलेगी. राजकीय सहयोग प्राप्त होगा.

कर्क- व्यापारिक साझेदारी लाभदायी रहेगी. घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिये कर्ज लेना पड़ सकता है. सुख सुविधाओं की पूर्ति होगी. संपर्क सूत्र बढेंगे. यश मिलेगा.

सिंह- वाणीं पर नियंत्रण रखें. अधिकारी काम की आलोचना करेंगे. परिणय चर्चाओं में सफ्लता के आसार हैं. श्रम से अधिक कार्य करना पड़ेगा. पराक्रम बना रहेगा.

कन्या- यात्रा स्थगित करनी पड़ेगी. सबकी सलाह से आगे बढ़ना लाभदायी रहेगा. व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा. विवादों को टालना हितकर रहेगा.

तुला- व्यापारिक लेन-देन में सावधानी बरतें, धोखा हो सकता है. झूठ बोलकर मुश्किल में पड़ सकते हैं. पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा. मित्रता लाभदायक सिद्ध होगी.

वृश्चिक- आत्मविश्वास की कमी से महत्वपूर्ण निर्णय लंबित होंगे. दूसरों की बातों में आकर अपनों को नाराज कर लेंगे. कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी.

धनु- अटके काम दोस्तों की मदद से पूरे होंगे. नया काम शुरू करेंगे. निर्माण संबंधी कार्यों में प्रगति होगी. संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेगा.

मकर- समय के साथ कार्यशैली में बदलाव करें. दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम स्वयं करें. साहस एवं पुरूषार्थ की वृद्धि होगी.

कुम्भ- मन की बात करीबी से कह देने से तनाव कम होगा. दूसरों के मामले में हस्तक्षेप से बचें. प्रिय अतिथि का आगमन होगा. समस्याओं का समाधान होगा.

मीन- पुरानी गलती उजागर होने से नीचा देखना पड़ेगा. विरोधियों से सावधान रहें. मनोरंजन, भ्रमण, आमोद प्रमोद के साधानों की पूर्ति होगी. लाभ होगा.

उदयकालीन ग्रह चाल

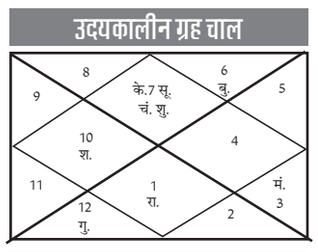

पंचांग

रा.मि. 26 संवत् 2082 माघ कृष्ण त्रयोदशी भृगुवासरे रात 10/10, मूल नक्षत्रे दिन-रात, ध्रुव योगे रात 9/44, गर करणे सू.उ. 6/42, सू.अ. 5/18, चन्द्रचार धनु, पर्व- प्रदोष व्रत, शु.रा. 9, 11, 12, 3, 5, 7 अ.रा. 10, 1, 2, 4, 6, 8 शुभांक- 2, 4, 8.

व्यापार भविष्य

माघ कृष्ण त्रयोदशी को मूल नक्षत्र के प्रभाव से गेहूं, जौ, चना, तिल, उड़द के भावों में मंदी होगी. सरसों, अरंडी, वनस्पति, घी, गुड, शक्कर के भाव में घटाबढ़ी रहेगी. जीरा, धनियां, लालमिर्च के भाव में समता रहेगी. वायदा विचार आज 11 बजकर 10 मिनिट के रूख पर व्यापार कर लाभ उठायें. भाग्यांक 7163 है.

SUDOKU 7275

9		2		4	1	7		
1						6		
5	7	3	2				4	
				9	4	8		
4		7				9		6
		5	8	3				
	3				6	5	9	1
		6						7
		9	1	8		2		4

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7274

5	4	9	1	8	3	2	6	7
1	2	6	4	9	7	3	5	8
3	8	7	5	2	6	1	4	9
8	7	1	3	4	2	6	9	5
9	5	3	6	1	8	7	2	4
2	6	4	7	5	9	8	1	3
4	3	5	2	7	1	9	8	6
6	9	2	8	3	4	5	7	1
7	1	8	9	6	5	4	3	2